नईदुनिया



देश के 3 बड़े बैंक डूबे तो देश की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हिल जाएगी

आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डी-सिब्स का दिया तमगा

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को देश के सबसे बड़े बैंकों यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपार्टेंट बैंक्स की लिस्ट जारी कर दी है। ये वह बैंक हैं यदि इनमें से किसी एक पर भी संकट आया या यह डूबा, तो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ सकती है। आरबीआई ने वर्ष 2026 के लिए भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-सिब्स बैंक का तमगा दिया है। ये तीनों बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं इन्हें टू बिग टू फेल यानी इतने बड़े कि डूब नहीं सकते माना गया है।

डी-सिब फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक देश के उन बैंकों की पहचान करता है, जिनका आकार, कारोबार और बैंकिंग सिस्टम में दखल इतना बड़ा है कि उनके विफल होने से पूरी अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। ऐसे बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई उन पर सामान्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा सख्त निगरानी रखता है। केंद्रीय बैंक ने 22 जुलाई 2014 को यह फ्रेमवर्क लागू किया था। इस सूची में सबसे पहले 2015 में एसबीआई को शामिल किया गया था। 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और 2017 में एचडीएफसी बैंक को डी-सिब बैंक का दर्जा मिला।

इन तीनों बैंकों को किसी भी आपातकालीन आर्थिक संकट या नुकसान से बचाने के लिए आरबीआई ने इनके लिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा कुछ अतिरिक्त पूंजी अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य किया है। 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के आधार पर तय नई श्रेणी में इन बैंकों की स्थिति पिछले साल जैसी ही रखी गई है।

सिब (बकेट-4): देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक को बकेट-4 में रखा गया है। इसके तहत एसबीआई को अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स के 0.80फीसदी के बराबर अतिरिक्त पूंजी बनाए रखनी होगी।

एसबीएफसी बैंक (बकेट-2): निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक को बकेट-2 में बरकरार रखा गया है, जिसके लिए 0.40फीसदी अतिरिक्त केट1 पूंजी रखना अनिवार्य है।

आईसीआईसीआई बैंक (बकेट-1): इसे बकेट-1 में रखा गया है और इसे अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के 0.20फीसदी के बराबर एक्स्ट्रा पूंजी सुरक्षित रखनी होगी। आरबीआई ने इन बैंकों के सिस्टम इंपार्टेंस स्कोर के आधार पर कुल पांच बकेट तय किए हैं।

इन बकेट्स के तहत बैंकों को 0.20फीसदी से लेकर 1फीसदी तक अतिरिक्त पूंजी रखनी होती है। बैंक जिस ऊंचे बकेट में होगा, उसे उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा। हालांकि, 2026 की सूची में किसी भी बैंक को बकेट-3 या बकेट-5 में शामिल नहीं किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

कोका-कोला या पेप्सी नहीं आजकल लोग का भा रहा लाहौरी जीरा, मसालों से है भरपूर



नई दिल्ली। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स कोका-कोला और पेप्सी की जगह लाहौरी जीरा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग इसे एक स्वस्थ विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह सोडा-आधारित होने के साथ-साथ जीरा और मसालों से भरपूर है, जो पाचन के लिए फायदेमंद है। इस देसी ड्रिंक की बढ़ती मांग ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। लाहौरी जीरा की कहानी 2017 में पंजाब के तीन चचेरे भाइयों, सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूटना की एक साधारण रसोई के प्रयोग से शुरू हुई। निखिल डोडा ने घर पर ही जीरे और मसालों से एक ठंडी, मसालेदार ड्रिंक बनाई, जिसका स्वाद तीनों भाइयों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया। परिवार से शुरुआती आर्थिक मदद मिलने के बाद, उनका यह छोटा सा प्रयोग करीब नौ सालों में एक बड़े ब्रांड में बदल गया। लाहौरी जीरा की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी किफायती कीमत भी है, क्योंकि इसकी एक बोतल सिर्फ 10 रुपए की है। यह देसी स्वाद और सोडा का अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, जो उन उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहा है जो कोल्ड ड्रिंक में कुछ अलग चाहते हैं। कम कीमत और देसी स्वाद के कारण यह छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बाजारों तक अपनी जगह बना रहा है। कंपनी के सीईओ सौरभ मुंजाल के मुताबिक पिछले साल कंपनी ने अपना उत्पादन दोगुना करके रोजाना 12 लाख बोतल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वह ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल उसका सालाना कारोबार 115 से 120 मिलियन डालर यानी करीब 1,112 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

चावल निर्यात पर 20 फीसदी ड्यूटी की तैयारी, घरेलू कीमतें होंगी स्थिर



नई दिल्ली। देश में बढ़ती महंगाई और चावल की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार चावल की कुछ विशेष किस्मों, खासकर टूटे चावल और महंगी गैर-बासमती चावल किस्मों के निर्यात पर 20 फीसदी तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। इस संभावित फैसले का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को स्थिर करना और उपभोक्ताओं पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करना है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत में खाने-पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता पर काफी आर्थिक बोझ पड़ा है। दाल, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। जानकारों के मुताबिक, देश के कुछ हिस्सों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में प्रीमियम गैर-बासमती चावल की कीमतों में उछाल आया है और इसकी उपलब्धता भी घटी है। इसके अलावा, टूटे चावल के दाम बढ़ने से पोल्ट्री और पशु चारे से जुड़े उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार का लक्ष्य है कि निर्यात पर अंकुश लगाकर घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे स्थानीय कारोबारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

बजाज पल्सर आरएस200 को नए अपडेट्स के साथ उतारा



नई दिल्ली। भारतीय बाजार में बजाज पल्सर आरएस200 को नए अपडेट्स के साथ उतारा गया है। नई पल्सर आरएस200 में अब इलेक्ट्रानिक थ्राटल बाडी, मल्टीपल राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और क्विकशिफ्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी ने इस स्पोर्ट्स बाइक में कई महत्वपूर्ण तकनीकी और फीचर संबंधी बदलाव किए हैं, जिससे राइडिंग अनुभव और भी बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। नए अपडेट्स से न केवल बाइक का प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों में चालक को अधिक नियंत्रण और सुरक्षा भी मिलती है। इसके अलावा, बाइक में 5 इंच का नया टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो पुराने कलर एलसीडी डिस्प्ले की जगह लेता है। यह नया डिस्प्ले गूगल मैप्स मिररिंग सुविधा के साथ आता है।

2027 तक सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव 4,650 डालर प्रति ट्राय औंस तक पहुंच सकता है

गोल्डमैन सैक्स ने सोने की इस संभावित तेजी के पीछे तीन प्रमुख वजहें बताई

नई दिल्ली

प्रमुख वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने सोने की कीमतों को लेकर एक बड़ा अनुमान जताया है। बैंक का मानना है कि वर्ष 2027 के आखिर तक सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव 4,650 डालर प्रति ट्राय औंस तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने सोने की इस संभावित तेजी के पीछे तीन प्रमुख वजहें बताई हैं, जिनमें सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीदारी, चीन द्वारा अपने सोने के भंडार में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना और भविष्य में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट में बैंक के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा कारण रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज किया जाना रहा है। इस घटना के बाद कई देशों ने अपने रिजर्व में सोने को ज्यादा महत्व देना शुरू किया है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2028 तक सेंट्रल बैंक हर महीने औसतन 60 टन सोना खरीद सकते हैं, जबकि 2022 से पहले यह औसत मात्र 17 टन प्रति माह था।

दूसरी वजह चीन की बढ़ती मांग है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है और उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी करीब 11.8 फीसदी है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि चीन भविष्य में इसे बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और मजबूत होगी। तीसरी प्रमुख वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले हैं। बैंक का अनुमान है कि दिसंबर 2026 और मार्च 2027 में ब्याज दरों में 0.25-0.25 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद जब ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू होगा, तो पश्चिमी देशों के निवेशकों की सोने में दिलचस्पी फिर से बढ़ेगी, जिससे कीमतों को और मजबूती मिलेगी।

गोल्डमैन सैक्स ने चांदी के मुकाबले सोने को ज्यादा मजबूत समर्थन मिलने का भी अनुमान लगाया है, क्योंकि सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी करते हैं, जो चांदी को संस्थागत स्तर पर नहीं मिलता। बैंक ने 2028 के अंत तक सोने का भाव 5,600 डालर प्रति ट्राय औंस तक पहुंचने का अनुमान है।



ट्रंप के दबाव में दोबारा सीईओ नहीं बना, बोर्ड ने गहन जांच के बाद लिया फैसला, एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग ने वापसी को लेकर चल रही खबरों का किया खंडन

नई दिल्ली। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने कंपनी में अपनी वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने उन सभी खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उन्हें दोबारा सीईओ बनाया गया है। जेन्सेन हुआंग ने साफ किया कि कंपनी के बोर्ड ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों की गहन जांच के बाद यह फैसला लिया और उनकी वापसी कंपनी और उसके शेयरधारकों के हित में थी। कर्मचारियों के साथ अपनी पहली बैठक में जेन्सेन हुआंग ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनके व्यवहार से उनकी पत्नी लोरी, बच्चों और कंपनी के कर्मचारियों को दुख पहुंचा है। उन्होंने अपनी बेवफाई की बात कबूल की और बताया कि वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रतिदिन 90 मिनट की थेरेपी ले रहे हैं। हुआंग ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी पूरी तरह राजनीति से दूर है, हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की एनवीडिया के प्रति प्रशंसा की सराहना की। इस बैठक में जेन्सेन ने कर्मचारियों को कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी का यह मतलब नहीं है कि किसी को भी नियमों को तोड़ने की छूट मिल गई है, और कंपनी के नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जेन्सेन हुआंग की वापसी के बाद एनवीडिया के शेयर 31फीसदी तक उछले थे, लेकिन अगले ही कारोबारी दिन इनमें करीब 7फीसदी की गिरावट आ गई। इस गिरावट का असर व्यापक अमेरिकी शेयर बाजार पर भी पड़ा। एआई उद्योग को लेकर बढ़ती चिंताएं और अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाने की आशंका के कारण नैस्डैक 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 3फीसदी तक टूट गया और अंत में 2फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 में भी 0.5फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई।

नहीं बढ़े घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम, उपभोक्ताओं को राहत



नवंबर की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हुई थी बढ़ोतरी

नई दिल्ली

बुधवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, नवंबर की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब भी 942 रुपए में मिल रहा है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,820 रुपए हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में नवंबर की शुरुआत में दिल्ली में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि मुंबई में 10.50, कोलकाता में 17 और चेन्नई में 11.50 रुपए का इजाफा हुआ था।

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों जैसी व्यावसायिक जगहों पर होता है। ऐसे में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी से कारोबारियों की लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर बाहर खाना खाने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बड़ी बढ़ोतरी मार्च 2026 में हुई थी, जब 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 60 रुपये का इजाफा किया गया था। इसके बाद जून में भी कीमतों में बदलाव हुआ और दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपए का हो गया। नवंबर में घरेलू गैस के दाम स्थिर रखे गए हैं, जिससे फिलहाल घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के लिए ग्राहकों को पिछले महीने जितनी ही कीमत चुकानी पड़ रही है।

देश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम में अंतर देखने को मिलता है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 939.50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 2,820 रुपए में उपलब्ध है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 2,774.50 रुपए का है। इसी तरह, पटना में घरेलू सिलेंडर 1,031.50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 3,110.50 रुपए का है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 2,932.50 रुपए में मिल रहा है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के ताजा रेट की जानकारी के लिए तेल कंपनियों की वेबसाइट देखें।

सीतारमण ने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विशेषज्ञों के साथ की बैठक



नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और खेल क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ बुधवार को केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 12वीं पूर्व-बजट परामर्श बैठक में स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और खेल क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ चर्चा की गई। अगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए आयोजित बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिवों; खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी भाग लिया, ताकि बजट बनाते समय देश की प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जा सके। वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट से पहले उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों, राज्य सरकारों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बजट पूर्व परामर्श बैठकें करता है, ताकि बजट में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के सुझावों को शामिल किया जा सके।

क्विक-कामर्स डिलीवरी बाय ने पहले महीने में ही कमाए 39,000, सुनकर सब हैरान

नई दिल्ली

क्विक-कामर्स प्लेटफार्म्स के जरिए 10 मिनट में सामान आप तक पहुंचाने वाले डिलीवरी बायज की कमाई को लेकर अक्सर चर्चा होती है। हाल ही में चंडीगढ़ के एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ने अपने पहले महीने की कमाई का खुलासा करके लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पहले महीने में करीब 39,000 रुपए कमाए हैं, जो कि कई पारंपरिक नौकरियों से ज्यादा है। यह डिलीवरी पार्टनर, जिन्होंने अपनी पहचान गोपनीय रखी, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपना अनुभव साझा किया।

उन्होंने बताया कि पहले महीने की नौकरी का अनुभव काफी अच्छा रहा और उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं आई। आमतौर पर वह सप्ताह के दिनों में करीब 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन सप्ताहांत में ग्राहकों के आर्डर बढ़ जाने के कारण उनकी शिफ्ट करीब 16 घंटे तक खिंच जाती है। इस कमाई में डिलीवरी शुल्क के साथ-साथ ग्राहकों से मिलने वाली टिप भी शामिल है। डिलीवरी पार्टनर ने उन लोगों को कुछ अहम सलाह भी दी है, जो डिलीवरी बाय बनने के बारे में सोच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आप इस काम में उतरने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लें। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ जैसे विकसित और संपन्न शहर में, जहां अच्छी खासी टिप मिलती है, इलेक्ट्रिक बाइक से काम करना काफी आसान हो जाता है और ईंधन का खर्च भी बचता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह काम शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला हो सकता है। 12 से 16 घंटे की लंबी शिफ्ट उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं।

यह मामला क्विक-कामर्स प्लेटफार्म पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की आय और उनके काम की परिस्थितियों पर नई रोशनी डालता है, साथ ही गिग इकोनामी में अवसरों और चुनौतियों को भी दर्शाता है।

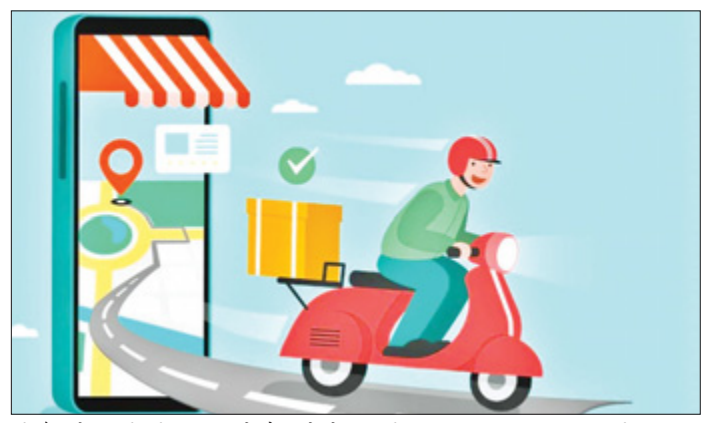

बान्ड बाजार में उतार-चढ़ाव: छोटी अवधि का पैसा कहां लगाएं, जानें सही रास्ता

निवेश से पहले सावधान, एग्जिट लोड और क्रेडिट जोखिम को समझें

नई दिल्ली

हाल के दिनों में बान्ड बाजार में जारी उतार-चढ़ाव ने निवेशकों के लिए छोटी अवधि के निवेश विकल्प चुनने की चुनौती बढ़ा दी है। जिन निवेशकों के पास अगले तीन महीने से एक साल तक के लिए अतिरिक्त फंड है, वे अक्सर बैंक एफडी और विभिन्न डेट म्यूचुअल फंड जैसे लिक्विड, अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड के बीच असमंजस में रहते हैं। ऐसे माहौल में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी जरूरत और निवेश की अवधि के हिसाब से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। बान्ड बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेश पर असर पिछले कुछ महीनों में बान्ड यील्ड में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 10 साल के सरकारी बान्ड की यील्ड 24 जुलाई को 6.84 फीसदी थी, जो 23 अक्टूबर तक बढ़कर 7.52 फीसदी पहुंच गई और 13 नवंबर को घटकर 7.34 फीसदी रह गई। बान्ड यील्ड बढ़ने से पहले से जारी बान्ड की कीमतें गिरती हैं, जिसका सीधा असर डेट फंडों के रिटर्न पर पड़ता है। वहीं, डेट म्यूचुअल फंड में निवेश का ट्रेंड भी अस्थिर रहा है, अक्टूबर में 1.13 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया, जबकि सितंबर में 1.83 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। ऐसे में निवेशकों को सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप एक से तीन महीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इनमें ब्याज दरों में बदलाव का असर आमतौर पर कम होता है और पैसा निकालने की सुविधा भी मिलती है। ये फंड अधिकतम 91 दिनों की मैच्योरिटी वाले साधनों में निवेश करते हैं, जिससे अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न की संभावना रहती है।



हालांकि, इनमें शुरुआती छह दिनों में पैसा निकालने पर एग्जिट लोड लग सकता है और ओवरनाइट फंड के मुकाबले थोड़ा क्रेडिट जोखिम हो सकता है क्योंकि ये कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट जैसे साधनों में भी निवेश करते हैं। वहीं बहुत कम अवधि, खासकर अगर आपको एक हफ्ते के भीतर पैसों की जरूरत है, तो ओवरनाइट फंड सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। इनमें जोखिम लगभग न के बराबर होता है, हालांकि रिटर्न लिक्विड फंड से थोड़ा कम हो सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि ब्याज दरें बढ़ने के माहौल में लिक्विड और ओवरनाइट फंड दोनों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इनके निवेश साधन जल्दी मैच्योर होते हैं और रकम नई, ऊंची ब्याज दरों पर दोबारा निवेश की जा सकती है। निवेशकों को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और सटीक निवेश अवधि के आधार पर ही इन विकल्पों का चुनाव करना चाहिए।